

Fourteenth Loksabha**Session : 6****Date : 23-12-2005****Participants : Agarwal Shri Dharendra**

>

Title : Need to ensure involvement of local MPs in the Centrally Sponsored Schemes.

डॉ. धीरेन्द्र अग्रवाल (चतरा) : अध्यक्ष महोदय, देश के विकास एवं लोगों को सुविधायें दिलाने हेतु केन्द्र सरकार की कइ प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, उनका फायदा लोगों को हो एवं आबंटित राशि का पूरा उपयोग हो रहा है या नहीं इसके लिए केन्द्र सरकार ने कोई निर्देश नहीं दिये हैं, जिसके कारण इन योजनाओं के लिए आबंटित होने वाली पैसे का केवल 15 से 20 प्रतिशत ही इन कामों पर खर्च हो रहा है। इन कार्यों को करने में स्थानीय सांसदों के सुझावों को नहीं माना जाता है और राज्य सरकार के अफसर अपने तरीके से काम करते हैं जो उनको सुविधाजनक होता है। राज्यों में जो राज्यों की तरफ से योजनाएं चलायी जाती हैं उसमें स्थानीय विधायकों की राय एवं सुझाव माने जाने हेतु राज्य सरकारों के निर्देश हैं, परन्तु केन्द्र सरकार की प्रायोजित योजनाओं में स्थानीय सांसदों की बात नहीं मानी जाती है जिसका प्रभाव यह होता है कि राज्य की अनपढ़ एवं कम पढ़े लिखे लोग समझते हैं कि उनके लिए केन्द्र सरकार कुछ भी नहीं कर रही है केवल राज्य सरकार ही उनके लिए काम कर रही है। केन्द्र सरकार कइ गैर सरकारी संगठनों को कइ योजनाओं को लागू करने हेतु केन्द्र स्तर पर पैसा देती है उनमें भी सांसदों की कोई भूमिका नहीं है और न ही उनकी कोई राय मानी जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो योजनाएं सांसदों के क्षेत्र में चल रही हैं और निगरानी एवं सतर्कता कमेटी के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की हैसियत से राज्य सरकार के अधिकारियों की शिकायतें केन्द्र सरकार को करते हैं वह भी राज्य सरकार के अधिकारियों को जांच हेतु भेजी जाती हैं जोकि न्यायसंगत नहीं है।

सदन के माध्यम से प्रधान मंत्री जी से अनुरोध है कि केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में स्थानीय सांसद की राय लेने का नियम बनाया जाये।